



सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 लाख गैर-सरकारी संगठनों के ऑडिट का आदेश

सन्दर्भ

वार्षिक लेखा-जोखा न देने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सरिफ काली सूची में डालने को अपर्याप्त बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऐसे एनजीओ के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने का भी नरिदेश दिया है। साथ ही, शीर्ष अदालत ने सरकार को देश भर के करीब 32 लाख गैर-संगठनों के खातों की ऑडिट करने का नरिदेश दिया है। इसके अलावा, न्यायालय ने सरकार से ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के लिये भी कहा है।

महत्त्वपूर्ण बढि

मुख्य न्यायमूर्ति जे.ए.स खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा सार्वजनिक कोष की अनयिमतिता में शामिल होने और वार्षिक लेखा-जोखा न देने वाले एनजीओ को सरिफ काली सूची में डालना पर्याप्त नहीं है। पीठ ने सरकार को ऐसे एनजीओ के खिलाफ कोष की अनयिमतिता और रकम की वसूली की कार्रवाई करने का नरिदेश दिया है।

- पीठ ने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों को मलिनने वाला फंड वास्तव में आम लोगों का पैसा होता है, लहिाजा इसके दुरुपयोग की इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती, अतः प्रत्येक एनजीओ को अपना वार्षिक लेखा-जोखा देना ज़रूरी है।
- न्यायालय ने एनजीओ को मलिनने वाले सरकारी फंड की नगिरानी के लिये प्रभावी तंत्र न बनाने पर केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। गौरतलब है कि इस समय देश भर में करीब 33 लाख एनजीओ हैं, जनिमें से केवल तीन लाख एनजीओ ने ही अपना ऑडिटड लेखा-जोखा सरकार के पास जमा कयिा है।
- न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि एनजीओ की मान्यता के लिये वह नयिम बनाए तथा उनके एकाउंट्स आदिका प्रबंधन करने के लिये दशानरिदेश तय करे और न्यायालय को इसकी जानकारी दे।
- गौरतलब है कि एनजीओ के ऑडिट की नगिरानी के लिये देश में अभी तक कसिी भी तंत्र का गठन नहीं कयिा गया है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/supreme-courts-audit-of-the-30-million-non-governmental-organizations>